P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika
E: ISSN NO.: 2349-980X Vol-III* Issue-V* January-2016

भू–सुधार के क्षेत्र में (भुंइया कार्यक्रम के अंतर्गत भू–अभिलेखों के कम्प्यूटरोकरण योजना की सफलता का एक अध्ययन (दुर्ग–जिले छ.ग. राज्य के विशेष संदर्भ में)

टी. आर. रात्रे
सहायक प्राध्यापक,
अर्थशास्त्र विभाग,
गुरूघासीदास विश्वविद्यालय,
बिलासपुर, छ.ग.

सारांश

विश्व के देशों जैसेः– यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ताइवान एवं मैक्सिको में भी भू–सधारों के द्वारा आर्थिक विकास किये गये है। भारत में कृषि विकास की दृष्टि से जमीदारो प्रथा काफी दोषपूर्ण सिद्ध हुयी जिसके कारण कृषि उत्पादन बढ़ाना कठिन हो गया। अतः भारत में कृषि विकास के लिये भू–सुधार कार्यक्रम प्रारंभ किया गया परन्तु भारत के अधिकांश राज्यों में भूमि संबंधी रिकार्ड व्यवस्थित एवं अद्यतन नही था अतः भारत सरकार ने भूमि संबंधी रिकार्ड को कम्प्यूटरीकरण करने की निर्णय लिया गया तथा 1988–89 से भूमि संबंधी रिकार्ड का कम्प्यूटरीकरण करने हेतु कार्य प्रारंभ किया गया।)

मुख्य शब्द : भुंइया कार्यक्रम, कम्प्यूटरीकरण योजना।

प्रस्तावना

नवगठित छ.ग. राज्य ने 01 नवम्बर 2000 को भू–सुधार के क्षेत्र में भू–अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण करने का प्रारंभ किया गया जिसे ''भुइंया कार्यक्रम'' का नाम दिया गया।

वर्तमान मे यह योजना भारत सरकार ने 582 जिलों में लागू किया गया है। वर्ष 1997–1998 में इस योजना को तहसील स्तर पर लागू करने का निर्णय लिया गया, जिससे कि आम लोगों को कम्प्यूटरीकृत भूमि रिकार्ड उपलब्ध कराने में सुविधा हो सकें।

31 मार्च 2000 तक 569 जिले के लगभग 2426 तहसीलों में लागू की गई। छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में पाटन तहसील, बिलासपुर जिले में मरवाही तहसील, एवं बस्तर जिले में कोंडागाँव में प्रारंभ किया गया।

कृषकों की भूमि संबंधी रिकार्ड को कम्प्यूटरीकरण करना एक चुनौती पूर्ण कार्य था। छत्तीसगढ़ शासन ने भू–अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण कार्य को पूर्ण करने हेतु प्रत्येक गांव के भूमि संबंधी रिकार्डो जैसेः– खसरा एवं बी–1 को कम्प्यूटर में दर्ज कराए गए तथा रिकार्ड सही तथा अद्यतन हो इसके लिये पटवारी, राजस्व निरीक्षक, अधीक्षक, तहसीलदार, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं जिला कलेक्टर के कुशल निर्देशन में यह कार्य जांच कराकर भू–अभिलेखों का रिकार्ड कम्प्यूटराईज किये गये। इसके पश्चात कृषकों को उनके भूमि संबंधी रिकार्ड का कम्प्यूटरीकृत प्रतिलिपि दिया गया। यह कार्यक्रम, केवल छ.ग. राज्य में ही नही बल्कि हमारे देश में तीसरा राज्य है, इसके पूर्व में कर्नाटक एवं गोवा राज्य में भू–अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण कार्य प्रारंभ कराया गया था। ये दोनों राज्यों में खसरा एवं बी–1 का कम्प्यूटरीकरण किया गया है किन्तु छत्तीसगढ एक ऐसा राज्य है जहाँ खसरा, बी–1 का कम्प्यूटरीकरण के साथ–साथ नक्शे का भी डिजिटाइजेशन का कार्य ISSRO (NAGPUR) द्वारा पूर्ण कराया गया है तथा इस कार्य में चिप्स एवं NIC संचालनालय (छत्तीसगढ़ शासन) का मार्गदर्शन बहुमूल्य रहा है।

यह कार्यक्रम बहुत जटिल एवं चुनौतिपूर्ण था। छत्तीसगढ़ शासन ने 06 वषा में पूर्ण कर लिया जो कि एक बड़ी उपलब्धि रही है।

दुर्ग जिले की गठन 01 जनवरी 1906 को हुआ। यह जिला नवगठित छ.ग. राज्य के पूर्व में $21^0$21 पूर्व से $22^0$02 पूर्व अक्षांश और 80^0–80 पूर्व में 81^0–58 पूर्व देशान्तर तक फैला हुआ है समुद्रतल से इसकी ऊँचाई 317 मीटर है। कुल क्षेत्रफल 870180 हेक्टेयर है जिसमें राजस्व क्षेत्रफल 795269 हेक्टेयर एवं वन क्षेत्रफल 76911 हेक्टेयर है। खाते का क्षेत्रफल 613671 हेक्टेयर एवं गैर खाते का क्षेत्रफल 256509 हेक्टेयर है। खरीफ मौसम का क्षेत्रफल 488599

हेक्टेयर तथा रबी मौसम का क्षेत्रफल 321266 हेक्टेयर है। जिले का कुल जनसंख्या 2810436 लाख (2001 जनगणना) थी।

शोध का उद्देश्य

1. भू–अभिलेखों का अद्यतीकरण करना एवं दस्तावेजों को सुरक्षित रखना।
2. कृषकों को उनके भू–अभिलेखों की कम्प्यूटरीकृत प्रतिलिपि प्रदान करना।
3. भुंइया कायक्रम को विश्वसनीय एवं सफल बनाने हेतु सुझाव देना।

शोध का महत्व

1. भारत में भूमि सुधार कार्यक्रमों को लागू करने की दिशा में भू–अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण एक नवीन एवं विश्वसनीय प्रयास है।
2. भू–धारको की अभिलेख विश्वसनीय एवं सुरक्षित रखी जा सकेगी। कृषकों क रिकार्ड संबंधित जानकारी सरल हो जायेगी।
3. भूमि की क्रय–विक्रय से प्रतिमाह संशोधित रिकार्ड की कम्प्यूटर में रिकार्ड अद्यतन की जा सकेगी।
4. कृषकों को अनावश्यक पटवारियों, राजस्व अधिकारियों का चक्कर नही काटना पड़ेगा तथा समय पर एवं न्यूनतम मूल्य पर उन्हें उनके खसरा, बी–1, एवं नक्शे की कम्प्यूटरीकृत प्रतिलिपि उपलब्ध हो सकेगा।
5. भू–अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण से भू–अभिलेखों एवं बिचौलियों से छुटकारा मिल सकेगा।
6. कम्प्यूटरीकरण से पूर्व पटवारी बस्ते में उपलब्ध रिकार्ड जीण–शीर्ण हो चुके थे। अब कम्प्यूटरीकृत कार्य पूर्ण होने क रिकार्ड दीर्घकाल तक सुरक्षित रखा जा सकता है।
7. किसी भी ग्राम के भू–अभिलेखों के रिकार्ड में पटवारी एवं अन्य राजस्व अधिकारियों द्वारा हेरा–फेरी नही कर सकेगा।

तालिका

दुर्ग जिले (छत्तीसगढ़ राज्य) की भू–अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण कार्य की तहसीलवार जानकारी

क्र.	अनुविभाग की नाम	तहसील का नाम	कुल ग्रामों की संख्या	कुल खसरा नंबर	बी–1	कुल नक्शे 'शीट्स की संख्या
1	दुर्ग	1. दुर्ग	106	218136	102242	282
		2. धमधा	173	253277	54616	431
2	पाटन	3. पाटन	157	192284	48235	391
		4. भुण्डरदेही	163	229273	60252	355
3	बेमेतरा	5. बेमेतरा	192	195497	45672	373
		6. नवागढ़	188	100674	29822	324
4	साजा	7. साजा	191	200230	45918	367
		8. बेरला	137	193543	50614	362
5	डौडीलोहारा	9. डौडीलोहारा	210	196985	44485	484
6	बालोद	10. बालोद	199	186032	47020	442
		11. गुरूर	114	158537	46890	191
		11 तहसील	1830	2124488	575766	4002

स्त्रोत कार्यालय कलेक्टर भू–अभिलेख शाखा दुर्ग वर्ष 2007–2008

निष्कर्ष

भारत ही नहो बल्कि विश्व के विकसित देशों–यरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ताइवान आदि देशों में भू–सुधारो के द्वारा आर्थिक विकास किये है, भारत के अधिकांश राज्यो ने भू–सूधार कार्यक्रम के तहत् भू–अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण की दिशा में अग्रणी प्रयास जारी है। परिणामतः इस कार्यक्रम के द्वारा कृषको, तथा आम–आदमी को अपने भू–अभिलेखों की वास्तविक रिकार्ड के बारे में आसानी से जानकारी पाप्त हो रही है, तथा इससे भू–संबंधी विवादों में भी कमी हुई है। जिलास्तर, तहसील, विकासखंड तथा पटवारी हल्के स्तर पर भी भू–अभिलेखों की कम्प्यूटरीकरण की नक्शा, खसरा एवं बी–1, अर्थात पी–1 एवं पी–2 का कम्प्यूटरीकृत प्रतिलिपि (5 प्रतिशत पेज) की दर से उपलब्ध करायी जा रही है जो कि सरकार का यह कार्यक्रम एक सराहनीय कदम है जिससे समाज व राष्ट्र निश्चित ही लाभान्वित होगें, और यह कार्यक्रम अन्य देशों के लिए भी अनुकरणीय साबित होगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. मिश्र एस.के. एवं पुरी वी.के. ''भारतीय अर्थव्यवस्था'' पृष्ठ क्रमांक 361–376 हिमालय पब्लिकेशन नई दिल्ली।
2. दत्त रूद्र एवं सुन्दरम ''भारतीय अर्थव्यवस्था'' पृष्ठ क्रमांक 551-564 S.CHAND COMPANY LTD. NEW DELHI.
3. भुंइया कार्यक्रम वार्षिक तालिका – 7 एवं 09 कार्यालय कलेक्टर भू–अभिलेख शाखा दुर्ग वर्ष 2007–2008.